

प्रेषक,

राजीव गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक,
उत्तराखण्ड, देहरादून

गृह अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 13 सितम्बर, 2010

विषय:-जनपद देहरादून में विधि विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या: डीजी-दो-41(4)/2007 दिनांक 06 अक्टूबर, 2009 के क्रम में शासनादेश संख्या: 68/xx(1)/32/निर्माण/2007-2008 दिनांक 15 जनवरी, 2008 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून में विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था "लोक निर्माण विभाग" देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गये ₹ 80.92 लाख के पुनरीक्षित आगणन का तकनीकी परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 77.24 लाख पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त निर्माण कार्य हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 में अवशेष(समस्त) ₹ 29.09 लाख (रुपये उनतीस लाख नौ हजार मात्र) की धनराशि स्वीकृत करते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करना आवश्यक होगा।

3- कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

4- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।

5- एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

6- कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं

लो.नि.वि. द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

7- कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भौति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

8- निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लायी जाए।

9- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

10- निर्माण कार्य तथा इस हेतु सामग्री क्रय में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (Uttarakhand Procurement Rules), 2008 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण इकाई से M.O.U निष्पादित किया जाय जिसकी प्रति शासन को भी उपलब्ध करायी जाय।

11- निर्माण कार्य के प्रगति की निरन्तर समीक्षा करते हुए कार्य में शीघ्रता लायी जाय तथा विलम्ब के कारण किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।

12- स्वीकृत धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए किया जाय तथा व्यय उन्ही मदों में किया जाय जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।

13- निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए सम्बन्धित निर्माण संस्था उत्तरदायी होगी। कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल एवं तद्विषयक समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

14- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय, आयोजनागत, 211-पुलिस आवास, 04-पुलिस विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण हेतु मानक मद-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

15- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या:-83P/xxvii(5)/2010 दिनांक 01 सितम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव

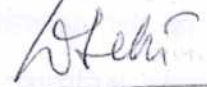
क्रमशः.....3

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तदनुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, उत्तराखण्ड।
3. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार, 25 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. बजट अधिकारी, बजट निदेशालय, सचिवालय परिसर देहरादून।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र(एन.आई.सी.) सचिवालय परिसर देहरादून।
8. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-5/नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(दीपम सेठ)

अपर सचिव